ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हुए एमओयू को सितंबर-अक्तूबर की चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरमनी में अमली जामा पहनाया जाएगा

वेयरहाउस की 40 परियोजनाएं इस वर्ष शुरू होंगी

तैयारी

लखनऊ, विशेष संवाददाता। उत्तर प्रदेश में वेयरहाउस व लाजिस्टिक के क्षेत्र में जल्द बड़ा निवेश दिखने जा रहा है। इसी साल 40 से ज्यादा कंपनियां अपनी परियोजनाएं चालू कर देंगी। इन कंपनियों में सभी ने जमीन का इंतजाम कर लिया है और इनमें कई ने तो जमीन पर निर्माण भी शुरू कर दिया है। इन सबका शिलान्यास सितंबर-अक्तूबर में होने वाली चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरमनी में कराया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे।

इन परियोजनाओं से राज्य की भंडारण क्षमता बढ़ेगी। यूपीसीडा वेयरहाउस व लाजिस्टिक के क्षेत्र में 156 परियोजनाओं को निवेश के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इन सभी ने इस साल फरवरी में हुए वैश्विक निवेश सम्मेलन में एमओयू किया था। जमीन की समस्या से जूझ रही कई कंपनियों को कई विकल्प दिए जा रहे हैं। इन्हें मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने तत्काल निस्तारण कराने को कहा है। यूपीसीडा को उम्मीद है कि अगले तीन महीनों में बाकी निवेशकों को भी जमीन उपलब्ध कराने से लेकर उनके दूसरे मसलों का समाधान करा लिया जाएगा।

06 परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है

03 माह में बाकी निवेशकों को भी जमीन उपलब्ध करा दी जाएगी

वेयरहाउसिंग व लॉजिस्टिक परियोजनाओं की स्थिति

कंपनी	निवेश	रोजगार	लोकेशन
ओसवाल बुक्स एंड लर्निंग	20.5	100	आगरा
आरईसी	20000	3000	बरेली
आर के लक्ष्मी लाजिस्टिक	250	50	संतकबीर नगर
श्री एसोसिएटस	30	900	गोरखपुर
साहू वेयरहाउस	10	20	बस्ती
मल्टी विंग्स इलेक्ट्रिक	500	800	गाजियाबाद
नीलम हाइड्रलिक	500	100	हापुड़
इंडो वर्ल्ड स्पेस	170	5000	हापुड़
लोगी इंटरनेशनल	150	5000	हापुड़
कैपिटल लाजिस्टिक	110	2000	हापुड़
नानक लाजिस्टिक	155.9	4000	लखनऊ
जाली वेयरहाउसिंग	60	400	लखनऊ
निर्माण शुरू			
अमृत कौर	26	350	लखनऊ
एवरग्रीन	50	50	लखनऊ
सात्विक लाजिस्टिक	100	20	गौतमबुद्धनगर
एरावत सुपरमार्ट	100	50	बुलंदशहर
बनारस बीडस	41	63	वाराणसी
विनायक ग्रुप	50	1000	उन्नाव

एक हजार निवेशकों के लिए भूमि उपलब्ध

लखनऊ, विशेष संवाददाता। उत्तर प्रदेश में 35 लाख करोड़ के निवेश को आकर्षित करने के बाद योगी सरकार की प्राथमिकता सभी निवेशकों को उनकी परियोजनाओं के लिए जमीन मुहैया कराने की है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से सरकार ने जो 22 हजार से अधिक निवेश करार किए हैं, उनमें से 1450 से ज्यादा एमओयू के लिए सरकार को भूमि अधिग्रहण के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। योगी सरकार ने प्राप्त अनुरोध के सापेक्ष 1000 से अधिक भूमि की उपलब्धता कर ली है। जल्द ही बाकी एमओयू के लिए भी भूमि उपलब्ध होने की उम्मीद है।

दो एमओयू के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी: यूपीजीआईएस के दौरान ही सरकार की ओर से सभी विभागों को एमओयू के आधार पर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। सरकार के साथ एमओयू करने वाले 1450 से अधिक निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में परियोजना की शुरुआत के लिए सरकार से भूमि की मांग की है। बाकी बचे 400 से अधिक एमओयू के लिए भी युद्धस्तर पर भूमि उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से पहले ही योगी सरकार ने 2 एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली है। वहीं, 16 ऐसे निवेशक भी हैं, जिन्हें उनकी मांग के अनुरूप भूमि के विकल्प भी सुझाए गए हैं।

22 हजार से अधिक करार इन्वेस्टर्स समिट में हुए

- 1450 प्रोजेक्ट के लिए भूमि के अनुरोध प्राप्त हुए हैं
- नोएडा गाजियाबाद में भूमि की सबसे ज्यादा मांग

लखनऊ में दी गई है सबसे ज्यादा जमीन

गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद जैसे वेस्ट यूपी के इलाकों में सर्वाधिक भूमि की मांग है। हालांकि, मांग के सापेक्ष सबसे अधिक भूमि लखनऊ में उपलब्ध होने की जानकारी दी गई है। लखनऊ में 72 एमओयू के लिए भूमि की मांग की गई, जिसके सापेक्ष सर्वाधिक 46 भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है।

कई जनपदों में शत प्रतिशत भूमि उपलब्ध

लखनऊ के अलावा कई ऐसे जनपद हैं, जहां मांग के अनुरूप 100 प्रतिशत भूमि की उपलब्धता सुनिश्चत की जा चुकी है। ऐसे जनपदों में फतेहपुर (19), मऊ (10), चंदौली (12), हमीरपुर (11), महोबा (11), अंबेडकरनगर (10), फर्रूखाबाद (5), श्रावस्ती (4), सिद्धार्थनगर (4), बलिया (3), कौशांबी (2), लखीमपुर खीरी (2) और पीलीभीत (1) शामिल हैं। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एकमात्र कन्नौज है, जहां फिलहाल भूमि की मांग शून्य है। सरकार ने जो व्यवस्था की है, उसके अनुसार सभी जनपदों के डीएम को भूमि की उपलब्धता की जानकारी इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से निवेशकों को उपलब्ध करानी है।